

[2024] 3 एससीआर 1147 : 2024 आईएनएससी 223

अपूर्व अरोड़ा एवं अन्य आदि।

बनाम

राज्य (रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार) एवं अन्य

(आपराधिक अपील सं. 1694-1695/2024)

19 मार्च 2024

[माननीय न्या. श्री ए.एस. बोपन्ना और माननीय न्या. श्री पामिदिघंटम श्री
नरसिम्हा*]

विचारणीय मुद्दा

क्या वेब-सीरीज़ 'कॉलेज रोमांस' के एपिसोड के शीर्षक और जानकारी में अपशब्दों और अपवित्र भाषा का उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67 क के तहत अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण का अपराध है।

हेडनोट्स

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – उप-धारा 67, 67क – दंड संहिता, 1860 – धारा 292 – अश्लीलता – परीक्षण – शिकायत दर्ज की गई कि वेब-सीरीज़ 'कॉलेज रोमांस' के सीज़न 1, एपिसोड 5, जिसका शीर्षक 'हैप्पीली एफ***डी अप' है, के शीर्षक और विभिन्न हिस्सों में अभद्र और अश्लील भाषा थी, जो अन्य बातों के साथ-साथ दंड संहिता, 1860 की धारा 292, 294, 509 और आईटी अधिनियम की उप-धारा 67, 67क के तहत अपराध का गठन करती है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण (वेब-सीरीज़ के अभिनेता, निर्माता आदि)

द्वारा उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश देने वाले अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी और अति.सत्र.न्या. के आदेशों को रद्द करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया, और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया - सत्यता:

अभिनिर्धारित किया गया - उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर सामुदायिक मानक परीक्षण लागू किया - हालांकि, इसने जांच के लिए गलत तरीके से प्रश्न तैयार किया कि क्या एपिसोड में इस्तेमाल की गई भाषा युवाओं द्वारा समकालीन रूप से इस्तेमाल की गई थी और क्या यह शालीनता की सीमा को पूरा करती है - आईपीसी की धारा 292 या आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत जांच इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि भाषा या शब्द सभ्य हैं या नहीं या क्या वे देश में आम तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं - बल्कि, जांच यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या जानकारी कामुक है, कामुक हितों को आकर्षित करती है, या उन लोगों के दिमाग को नष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है जिन तक इसके पहुँचने की संभावना है - उच्च न्यायालय ने पाया कि भाषा अपशब्दों, गालियों और अश्लील गालियों से भरी थी, जिन्हें खुली न्यायालय में नहीं सुना जा सकता था और माना कि जानकारी अश्लील थी क्योंकि यह संवेदनशील दिमागों को प्रभावित करने वाली और उन्हें भ्रष्ट कर देने वाली थी। विशिष्ट जानकारी जिसे अश्लील पाया गया, वह गंदी, अशिष्ट और अपवित्र भाषा थी - उच्च न्यायालय ने अपवित्रता और अशिष्टता को अश्लीलता के बराबर माना, बिना इस बात का समुचित या विस्तृत विश्लेषण किए कि ऐसी भाषा अपने आप में यौन, कामुक, अश्लील या भ्रष्ट करने वाली कैसे हो सकती है - अश्लीलता और गाली-गलौज अपने

आप में अश्लीलता नहीं है - अश्लीलता ऐसी जानकारी से संबंधित है जो यौन और कामुक विचारों को जगाती है, जो कि एपिसोड में प्रयुक्त अपमानजनक भाषा या गालियों का प्रभाव बिल्कुल नहीं है - यद्यपि प्रयुक्त शब्दों का शाब्दिक अर्थ यौन प्रकृति का हो सकता है और यौन कृत्यों को संदर्भित करता है, लेकिन उनका प्रयोग किसी भी सामान्य विवेक और सामान्य बुद्धि वाले दर्शक में यौन भावनाएं या वासना नहीं जगाता है - बल्कि, इन शब्दों का सामान्य उपयोग क्रोध, रोष, हताशा, दुःख या शायद उत्तेजना की भावनाओं को दर्शाता है - इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ लेते हुए, उच्च न्यायालय बड़ी वेब-सीरीज़ के संदर्भ में और "सामान्य ज्ञान और विवेक वाले एक साधारण व्यक्ति" के मानक के अनुसार विशिष्ट जानकारी (अशिष्ट भाषा) पर विचार करने में विफल रहा - युवा छात्रों के कॉलेज जीवन पर एक हल्के-फुल्के शो, वेब-सीरीज़ के कथानक और विषय के संदर्भ में जब ऐसी भाषा का उपयोग देखा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि इन शब्दों का उपयोग सेक्स से संबंधित नहीं था और इसका कोई यौन अर्थ नहीं था - न तो वेब-सीरीज़ के निर्माता का इरादा था कि भाषा को उसके शाब्दिक अर्थ में लिया जाए और न ही इसका एक समझदार दर्शक पर कोई प्रभाव पड़ेगा - अश्लीलता का निर्धारण करने के लिए जानकारी का विश्लेषण और जांच करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कानूनी दृष्टिकोण में स्पष्ट त्रुटि थी - निर्धारण के लिए मानक किसी किशोर या बच्चे का दिमाग या ऐसे प्रभावों के प्रति संवेदनशील कोई अति संवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकता - उच्च न्यायालय ने जानकारी के प्रभाव को मापने के लिए प्रभावशाली दिमाग के मानक का गलत तरीके से इस्तेमाल किया और इस प्रकार अश्लीलता के परीक्षण को सही ढंग से लागू करने में गलती की - आईटी अधिनियम की धारा 67, 67 क के

तहत कोई अपराध नहीं बनता - उच्च न्यायालय का निर्णय रद्द -
आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67क के तहत अपीलार्थीगण के
खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द कर दी गई। [पैरा 33-35, 37, 39, 48
और 49] -

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 – उप-धारा 67 – दंड संहिता,
1860 – धारा 292 – धारा 292 और धारा 67 में परिभाषित
अश्लीलता – अंतर:

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 292 और धारा 67 में "अश्लीलता" को
समान रूप से ऐसी जानकारी के रूप में परिभाषित किया गया है जो
कामुक है; या कामुक रुचि को आकर्षित करती है; या इसका प्रभाव
ऐसे व्यक्तियों को नष्ट और भ्रष्ट करने की ओर जाता है, जो सभी
प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या
सन्निहित जानकारी को पढ़, देख या सुन सकते हैं - हालांकि, उनके
बीच अंतर केवल इतना है कि धारा 67 एक विशेष प्रावधान है जो तब
लागू होता है जब अश्लील जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या
प्रसारित की जाती है - चूंकि, वर्तमान मामले में, कथित आपत्तिजनक
जानकारी एक वेब-सीरीज़ है, इसलिए मामले पर आईटी अधिनियम
की धारा 67 के तहत विचार किया जाता है, लेकिन अश्लीलता के लिए
धारा 292 के तहत निर्धारित वही परीक्षण लागू होगा, क्योंकि उस
संबंध में प्रावधानों को समान रूप से शब्दबद्ध किया गया है। [पैरा
12]

दंड संहिता, 1860 – धारा 292 – अश्लीलता – जानकारी यदि अश्लील
है – वस्तुनिष्ठ रूप से न्याय करने की प्रक्रिया और विधि – चर्चा की
गई।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 - धारा 67क - 'यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण' - धारा 67क जब आकर्षित न हो:

अभिनिर्धारित किया गया: वर्तमान मामले के तथ्य धारा 67क को आकर्षित नहीं करते हैं क्योंकि परिवादी की शिकायत अश्लील गालियों, अपशब्दों और गालियों के अत्यधिक उपयोग के बारे में थी - शिकायत में किसी भी 'यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण' का कोई आरोप नहीं था और इस तरह, धारा 67क आकर्षित नहीं होती है - उच्च न्यायालय ने इस बात का कोई कारण नहीं बताया कि वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए धारा 67क कैसे आकर्षित हुई - धारा 67क का अपराध नहीं बनता है। [पैरा 45, 46]

दंड संहिता, 1860 - धारा 292 - अश्लीलता - हिक्लिन परीक्षण; "सामुदायिक मानक परीक्षण" - चर्चा की गई - धारा 292 पर उदाहरणों का पता लगाया गया।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 - उपधारा 67क, 67 - स्पष्ट, कार्य, आचरण - 'अश्लीलता':

अभिनिर्धारित किया गया: धारा 67क किसी भी ऐसी जानकारी के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन, प्रसारण, प्रकाशन या प्रसारण को अपराध मानता है जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण शामिल हो - हालांकि तीन अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट, कृत्य और आचरण खुले अर्थ वाले हैं और व्यापक अर्थ को शामिल करने में सक्षम हैं, वाक्यांश को धारा 67 में दिए गए 'अश्लीलता' के संदर्भ में देखा जाना चाहिए - इस प्रकार, धारा 67क और धारा 67 के बीच एक संबंध हो सकता है - उदाहरण के लिए, यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण हो सकता है जो कामुक नहीं हो सकता है - समान रूप से, ऐसा कार्य या आचरण कामुक

हितों को आकर्षित नहीं कर सकता है - इसके विपरीत, एक कलात्मक या भक्ति रूप में प्रस्तुत यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण किसी व्यक्ति को भ्रष्ट करने की बजाय बिल्कुल विपरीत प्रभाव डाल सकता है। [पैरा 47]

उद्धृत निर्णयज विधि

शरत बाबू दिगुमर्ति बनाम सरकार (रा.रा.क्षे.दिल्ली) [\[2016\]](#)
[8 एससीआर 1015](#): (2017) 2 एससीसी 18: 2016
आईएनएससी 1131; अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल
राज्य [\[2014\]](#) [2 एससीआर 263](#): (2014) 4 एससीसी
257: 2014 आईएनएससी 75; समरेश बोस बनाम अमल
मित्र [\[1985\]](#) [पूरक 3 एससीआर 17](#): (1985) 4 एससीसी
289: 1985 आईएनएससी 205; बॉबी आर्ट इंटरनेशनल
बनाम ओम पाल सिंह हून [\[1996\]](#) [पूरक 2 एससीआर 136](#):
(1996) 4 एससीसी 1: 1996 आईएनएससी 595; के.ए.
अब्बास बनाम भारत संघ [\[1971\]](#) [2 एससीआर 446](#):
(1970) 2 एससीसी 780: 1970 आईएनएससी 200; रमेश
पुत्र चोटालाल दलाल बनाम भारत संघ [\[1988\]](#) [2 एससीआर](#)
[1011](#): (1988) 1 एससीसी 668: 1988 आईएनएससी 44;
साक्षी बनाम भारत संघ [\[2004\]](#) [पूरक 2 एससीआर 723](#):
(2004) 5 एससीसी 518: 2004 आईएनएससी 383;
संजय दत्त बनाम सीबीआई, बॉम्बे के माध्यम से राज्य
(द्वितीय) [\[1994\]](#) [पूरक 3 एससीआर 263](#): (1994) 5
एससीसी 410: 1994 आईएनएससी 371; गिरधारी लाल
गुप्ता बनाम डी.एच. मेहता (1971) 3 एससीसी 189: 1970
आईएनएससी 164; भारत संघ बनाम राजीव कुमार
[\[2003\]](#) [पूरक 1 एससीआर 597](#): (2003) 6 एससीसी
516: 2003 आईएनएससी 320; यूएस टेक्नोलॉजीज
इंटरनेशनल (पी) लिमिटेड बनाम आयकर आयुक्त [\[2023\]](#)

[4 एससीआर 382](#): (2023) 8 एससीसी 24: 2023 आईएनएससी 329; *देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य* [\[2015\] 7 एससीआर 853](#): (2015) 6 एससीसी 1: 2015 आईएनएससी 414; *रंजीत डी. उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य* [\[1965\] 1 एससीआर 65](#): एआईआर 1965 एससी 881, 1964 आईएनएससी 171; *श्री चंद्रकांत कल्याणदास काकोडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य* [\[1970\] 2 एससीआर 80](#): (1969) 2 एससीसी 687: 1969 आईएनएससी 202; *महानिदेशक, दूरदर्शन महानिदेशालय बनाम आनंद पटवर्धन* [\[2006\] पूरक 5 एससीआर 403](#): (2006) 8 एससीसी 433: 2006 आईएनएससी 558; *अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ* [\[2006\] पूरक 10 एससीआर 770](#): (2007) 1 एससीसी 143: 2006 आईएनएससी 995; *एस. खुशबू बनाम कन्नियाम्मल* [\[2010\] 5 एससीआर 322](#): (2010) 5 एससीसी 600: 2010 आईएनएससी 247; *एन. राधाकृष्णन बनाम भारत संघ* [\[2018\] 11 एससीआर 1](#): (2018) 9 एससीसी 725: 2018 आईएनएससी 784; *एनएस मदनगोपाल बनाम के. ललिता* [\[2022\] 15 एससीआर 649](#): 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 2030: 2022 आईएनएससी 1323 - संदर्भित किया गया।

विजेश बनाम केरल राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन केरल 854; *प्रमोद आनंद धूमल बनाम महाराष्ट्र राज्य* (2021) एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 34; *मजीश के. मैथ्यू बनाम केरल राज्य* 2018 एससीसी ऑनलाइन केरल 23374; *रितेश सिधवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य* 2021 एससीसी ऑनलाइन ऑल 856; *जयकुमार भगवानराव गोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य* 2017 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 7283; *जी वेंकटेश्वर राव बनाम एपी राज्य रिट याचिका 1420 ऑफ़*

2020; जयकुमार भगवानराव गोरे बनाम महाराष्ट्र राज्य
2017 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 7283; प्रमोद आनंद धूमल
बनाम महाराष्ट्र राज्य 2021 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 34;
एकता कपूर बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2020 एससीसी
ऑनलाइन मध्य प्रदेश 4581 - संदर्भित किया गया।

रोथ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका 354, यूएस 476
(1957); आर बनाम बटलर (1992) 1 एससीआर 452 -
संदर्भित किया गया।

अधिनियमों की सूची

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000; दंड संहिता, 1860; दंड प्रक्रिया
संहिता, 1973; स्त्री अशिष्ट रूपण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1986

खोजशब्दों की सूची

वेब-सीरीज़; अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट जानकारी का प्रकाशन और
प्रसारण; अश्लीलता; अपशब्द; अश्लील गालियां; अपवित्र भाषा;
अपवित्रता; यौन रूप से स्पष्ट जानकारी; अश्लील भाषा; गाली शब्द,
गंदी अभद्र भाषा; हिकलिन परीक्षण; "सामुदायिक मानक परीक्षण";
रद्द करना।

से उत्पन्न मामला

आपराधिक अपीलिय अधिकारिता: 2024 की आपराधिक अपील सं.
1694-1695

2020 के सीआरएलएमसी सं. 2399 और 2215 में नई दिल्ली में
दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 06.03.2023 से
के साथ

2024 की आपराधिक अपील सं. 1697, 1696 और 1698

पक्षकारगण हेतु उपस्थिति

के.एम.नटराज, अति.महा.सा., मुकुल रोहतगी, साजन पूवैया, श्रीमती माधवी दीवान, हरीश साल्वे, वरिष्ठ अधिवक्तागण, अमीत नाइक, महेश अग्रवाल, अंकुर सहगल, सुश्री मधु गाडोदिया, सुश्री एस. लक्ष्मी अय्यर, चिराग नायक, सुश्री संजंती साजन पूवैया, अभिषेक कक्कर, देवांश श्रीवास्तव, सुश्री रक्षा अग्रवाल, सुश्री काजल दलाल, ई. सी. अग्रवाल, सुश्री मधु गाडोदिया, हर्षवर्द्धन झा, राघव शंकर, श्रीमती युगंधरा पवार झा, सुजॉय मुखर्जी, सुश्री तारिणी कुलकर्णी, अमन पाठक, सुश्री पल्लवी मिश्रा, श्रीकांत नीलप्पा तेरदाल, शरथ नांबियार, संजय कुमार त्यागी, श्रीधर पोटाराजू, सुश्री निधि खन्ना, कार्तिक जसरा, डॉ. अरुण कुमार यादव, अरविंद सिंह, उपस्थित पक्षकारगण हेतु अधिवक्तागण।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

माननीय न्या. श्री पमिदिघंटम श्री नरसिम्हा,

1. अनुमति प्रदत्त।
2. अपीलार्थी/अभियुक्त अभिनेता, कास्टिंग निर्देशक, पटकथा लेखक, वेब-सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के निर्माता और मीडिया कंपनी हैं, जो उस यूट्यूब चैनल का मालिक है जिस पर वेब-सीरीज होस्ट की गई थी। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 और 67क के तहत अश्लील और यौन-स्पष्ट जानकारी के उत्पादन, प्रसारण और ऑनलाइन प्रकाशन के लिए उनकी जांच और वाद चलाने की मांग की गई है। अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा उनके खिलाफ

प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के तहत अपीलार्थीगण की याचिका को उच्च न्यायालय ने हमारे समक्ष दिए गए आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। मामले पर विस्तार से विचार करने और निम्नलिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, हमने अपील को स्वीकार कर लिया है, उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द कर दिया है, और आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क के तहत अपीलार्थीगण के खिलाफ दिल्ली के मुखर्जी नगर पुलिस स्टेशन में दिनांक 16.04.2023 को दर्ज प्राथमिकी सं. 403/2023 को रद्द कर दिया है।

3. तथ्य: वर्तमान अपील दायर करने से संबंधित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं:

3.1 सहायक पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रतिवादी सं. 2 द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी कि वेबसीरीज के सीजन 1, एपिसोड 5, जिसका शीर्षक 'हैप्पीली एफ****डी अप' है, उसके शीर्षक और एपिसोड के विभिन्न हिस्सों में अश्लील और अभद्र भाषा है, जो भारतीय दंड संहिता की धाराओं 292, 294 और 509, आईटी अधिनियम की धाराओं 67 और 67 क और महिलाओं के अशिष्ट प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धाराओं 2 (ग) और 3 के तहत अपराध का गठन करती है। दिनांक 13.03.2019 को, परिवादी ने प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए एसीएमएम के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 156 (3) के साथ धारा 200 के तहत एक आवेदन दायर किया। जांच अधिकारी ने जांच की और दिनांक 09.04.2019 को कार्रवाई रिपोर्ट दायर की, जिसमें कहा गया कि कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है और वास्तव में, कथित आपत्तिजनक जानकारी में कोई अश्लीलता नहीं है।

- 3.2 हालांकि, एसीएमएम ने दिनांक 17.09.2019 के आदेश से परिवादी के आवेदन को स्वीकार कर लिया और अपीलार्थीगण के खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 292 और 294 और आई. टी. अधिनियम की धारा 67 और 67क के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया क्योंकि इस्तेमाल की गई अश्लील भाषा प्रथमदृष्टया दर्शकों के हितों को आकर्षित करने में सक्षम है और इसलिए अश्लील है।
- 3.3 अपीलार्थीगण ने अपर सेशन न्यायाधीश के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की, जिन्होंने दिनांक 10.11.2020 के आदेश द्वारा एसीएमएम के आदेश को आंशिक रूप से संशोधित किया और [शरत बाबू दिगुमर्ति बनाम सरकार \(राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र\)](#) में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करके केवल आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।
- 3.4 इसके बाद अपीलार्थीगण ने उपरोक्त आदेशों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष दं.प्र.सं. की धारा 482 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे दिनांक 06.03.2023 के निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया। आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए बर्खास्तगी और परिणामी निर्देश के खिलाफ, सभी अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई है।
- 3.5 उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसरण में, अपीलार्थीगण के विरुद्ध दिनांक 16.04.2023 को आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67क के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
4. *उच्च न्यायालय का तर्क:* उच्च न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क का उद्देश्य साइबर

स्पेस में अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण को दंडित करना है। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या जानकारी अश्लील है, इसने 'सामुदायिक मानक परीक्षण' पर भरोसा किया, जैसा कि इस न्यायालय ने [अवीक सरकार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य](#) में निर्धारित किया था और विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों में इसका पालन किया था। इस परीक्षण को लागू करके, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित माना: सबसे पहले, एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के मानक को लागू करते हुए, इसने पाया कि इस प्रकरण में नागरिक भाषा का उपयोग नहीं किया गया था और इसमें अपवित्रता और अश्लील गालियों का अत्यधिक उपयोग किया गया था, और यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों का स्पष्ट वर्णन और संदर्भ था। जानकारी एक आम आदमी को कैसे प्रभावित करती है, इसका निर्धारण भारतीय संदर्भ में, भारतीय नैतिकता के अनुसार, सभ्यता और नैतिकता के समकालीन मानकों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। कथित रूप से आपत्तिजनक भाग में (सीजन 1, एपिसोड 5 में 5:24 से 6:40 मिनट और 25:28 से 25:46 मिनट तक), पुरुष नायक, महिला नायक के साथ बातचीत में पुरुष और महिला जननांगों और यौन कृत्यों का वर्णन करने वाले शब्दों का उपयोग करता है, जिससे वे यौन रूप से स्पष्ट हो जाते हैं और कामुक भावनाएं पैदा होती हैं। जबकि महिला नायक को भाषा पर आपत्ति जताते और उस पर घृणा व्यक्त करते हुए सुना जाता है, वह पुरुष नायक के सामने वही बातें दोहराती है। इसके बाद पुरुष नायक और भी अधिक अश्लील गालियों और अभद्र भाषा का उपयोग करता है, जिसे महिला नायक द्वारा एपिसोड के बाद के भाग में दोहराया जाता है। उच्च न्यायालय ने माना कि यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का चित्रण आवश्यक रूप से फिल्मांकन के माध्यम से नहीं होता है, बल्कि बोली जाने वाली भाषा के माध्यम से भी हो सकता है। यह पाया गया कि जिन व्यक्तियों के प्रभावित

होने की संभावना है या जिन व्यक्तियों को ऐसी जानकारी भ्रष्ट या भ्रष्ट कर सकती है, वे वर्तमान मामले में संवेदनशील दिमाग वाले हैं, क्योंकि ऐसा कोई अस्वीकरण या चेतावनी नहीं है जो वेब-सीरीज़ को केवल 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए उपयुक्त के रूप में वर्गीकृत करता हो। बच्चों सहित जनता के लिए इसकी उपलब्धता को देखते हुए जानकारी शालीनता की सीमा को पार कर गई। इसके अलावा, न्यायालय ने महसूस किया कि लोगों को चौंकाए या भयभीत किए बिना और भाषा की मर्यादा बनाए रखने के लिए एपिसोड को न्यायालय कक्ष में नहीं सुना जा सकता।

5. दूसरा, यह प्रतिनिधित्व कि एपिसोड में इस्तेमाल की गई भाषा देश में और शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी के तहत संरक्षित नहीं है। तीसरा, यह कि ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटर और बिचौलिए सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि कंटेंट को सही ढंग से 'ए-रेटेड' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है और अपशब्दों और गालियों के इस्तेमाल के बारे में कोई चेतावनी नहीं दी गई है। अंत में, न्यायालय ने इस बात पर ध्यान दिया कि सार्वजनिक डोमेन और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील भाषा, अपशब्द और अपशब्दों को विनियमित किया जाना चाहिए क्योंकि वे कम उम्र के बच्चों जैसे संवेदनशील दिमागों के लिए खतरा हैं। इसके अलावा, यह प्रतिनिधित्व कि आम बोलचाल में ऐसी भाषा का इस्तेमाल "नया सामान्य" है, तथ्यों का विरूपण है क्योंकि यह अभी भी बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों की उपस्थिति में या धार्मिक स्थलों पर नहीं बोला जाता है। भाषाई नैतिकता को बनाए रखने के लिए, भाषाओं की पवित्रता और श्रद्धा की रक्षा की जानी चाहिए।

6. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थीगण की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि दं.प्र.सं. की धारा 154(3) के तहत अनिवार्य प्रक्रिया, जो एक महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक सुरक्षा है, का पालन धारा 156(3) का सहारा लेने से पहले नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक रूप से इस दलील को यह कहते हुए नकार दिया कि धारा 154(3) में केवल हो सकता है शब्द का इस्तेमाल किया गया है, करेगा नहीं, और परिवादी ने वैसे भी उत्तरी जिले के साइबर सेल के सहा.पु.आयु. से संपर्क किया, जो प्राथमिकी से उच्च अधिकारी हैं।

7. *अपीलार्थियों की प्रस्तुतियाँ:* हमने श्री मुकुल रोहतगी, श्री हरीश साल्वे, सुश्री माधवी दीवान, श्री साजन पूवय्या, वरिष्ठ अधिवक्तागण को सुना। अपीलार्थीगण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तागण ने तर्क दिया है कि वेबसीरीज के सीजन 1, एपिसोड 5 के कथित रूप से आपत्तिजनक हिस्से अश्लीलता की सीमा को पूरा नहीं करते हैं और उच्च न्यायालय ने जानकारी को अश्लील के रूप में चिह्नित करके गलती की है। इसके अलावा, इन हिस्सों में कोई भी यौन रूप से स्पष्ट कार्य नहीं है और इस तरह आईटी अधिनियम की धारा 67 या 67 क के तहत कोई अपराध नहीं बनता है। अपनी प्रस्तुतियाँ को विस्तार से बताते हुए, अपीलार्थीगण ने तर्क दिया:

7.1 आईटी अधिनियम की धारा 67, जो इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण को अपराध बनाती है, उस जानकारी को कवर करती है जो कामुक है या कामुक रुचि को अपील करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है कि उन लोगों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति है, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित जानकारी को पढ़, देख या सुन सकते हैं। अवीक सरकार (सुप्रा) के अनुसार, किसी जानकारी के अश्लील होने का निर्धारण 'सामुदायिक मानक परीक्षण' द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें

पूरे कार्य पर विचार किया जाता है और फिर उस विशिष्ट जानकारी को देखा जाता है जिसे पूरे कार्य के संदर्भ में अक्षील माना गया है। वेब-सीरीज़ एक रोमांटिक कॉमेडी है, जो कॉलेज में पढ़ने वाले दोस्तों के एक समूह की ज़िंदगी पर आधारित है। इसका उद्देश्य एक महानगरीय शहरी परिवेश में कॉलेज जीवन की एक प्रासंगिक तस्वीर पेश करना है। दो विशिष्ट हिस्से हैं जिन्हें अक्षील बताया गया है। पहला खंड वह है जहाँ पुरुष नायक, जिसका नाम बग्गा है, अंधाधुंध रूप से अपशब्दों का प्रयोग करता है जिसे नायरा नाम की महिला नायक सुनती है। नायरा इस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर आपत्ति जताती है और बताती है कि शब्दों का शाब्दिक अर्थ बेतुका है। बग्गा का कहना है कि इन शब्दों को शाब्दिक रूप से नहीं लिया जाना चाहिए और ये आम बोलचाल का हिस्सा हैं। नायरा अपनी असहमति दोहराती है और बग्गा को धमकी देती है कि अगर उसने इस तरह से बात करना जारी रखा तो उसे नतीजे भुगतने होंगे। बग्गा 'अनजाने में' एक और अपशब्द का इस्तेमाल कर देता है दूसरे भाग में, नायरा और बग्गा दोस्तों के एक बड़े समूह के साथ हैं, जहाँ नायरा एक अन्य दोस्त के बयानों से नाराज़ है और गुस्से में बग्गा के समान ही अपशब्दों का इस्तेमाल करती है, जिस पर बग्गा प्रसन्न होता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि जब इन दृश्यों पर व्यक्तिगत रूप से और संपूर्ण वेब-श्रृंखला के संदर्भ में विचार किया जाता है, तो वे अक्षील नहीं होते हैं। वे केवल इन शब्दों के शाब्दिक अर्थ की बेतुकीता को दर्शाते हैं और आम भाषा में उनकी अपरिहार्य उपस्थिति को दर्शाते हैं, जिसमें उनके उपयोग को अस्वीकार करने वाले लोग भी शामिल हैं।

- 7.2 समरेश बोस बनाम अमल मित्रा और बाँबी आर्ट इंटरनेशनल बनाम ओम पाल सिंह हून के मामले पर भरोसा करते हुए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि कथित हिस्से अश्लील हैं, लेकिन अश्लीलता अश्लीलता के बराबर नहीं है। केवल शब्दों को अश्लीलता नहीं माना जा सकता जब तक कि उनमें कामुक तत्व शामिल न हों जो यौन विचारों और भावनाओं को जगाते हैं, जो वर्तमान मामले में दृश्यों का प्रभाव नहीं है।
- 7.3 शब्दों के प्रभाव को "सामान्य बुद्धि और विवेक वाले सामान्य व्यक्ति", "उचित, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी" व्यक्ति के मानक से परखा जाना चाहिए, न कि किसी अतिसंवेदनशील व्यक्ति या कमजोर और अस्थिर दिमाग के दृष्टिकोण से। कथित रूप से आपत्तिजनक भागों में इस्तेमाल किए गए शब्द किसी भी यौन रूप से स्पष्ट कृत्य को संदर्भित नहीं करते हैं और सामुदायिक मानक परीक्षण के अनुसार अश्लील नहीं हैं। इसलिए, आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लीलता का कोई अपराध नहीं बनता है।
- 7.4 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया है कि दृश्यों में कोई यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण नहीं है, जैसा कि धारा 67 के तहत अपराध के लिए आवश्यक है। इस न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों पर भरोसा करते हुए, वे तर्क देते हैं कि दंड प्रावधान में शब्दों की सख्ती से व्याख्या की जानी चाहिए। 'यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण' शब्द में अपवित्रता/अश्लीलता/अपशब्द शामिल नहीं हैं, भले ही इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ यौन कृत्यों को संदर्भित करता हो। इन शब्दों के सामान्य उपयोग के माध्यम से शाब्दिक अर्थ अभिप्रेत नहीं है। बल्कि, वे निराशा, क्रोध और गुस्से जैसी भावनाओं की अभिव्यक्ति हैं।

- 7.5 विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने आईटी अधिनियम में 2006 के संशोधन विधेयक पर 50वीं स्थायी समिति की रिपोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालय के निर्णयों का भी हवाला देते हुए तर्क दिया है कि धारा 67क का उद्देश्य अश्लील जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण को अपराध बनाना है, जिसमें यौन कृत्यों को दर्शाया गया हो या जिसमें यौन रूप से स्पष्ट आचरण हो जो यौन कृत्यों के वास्तविक चित्रण से कम हो। चूंकि इस मामले में कथित खंडों में केवल अपशब्द हैं और यौन गतिविधि का कोई स्पष्ट दृश्य या मौखिक चित्रण नहीं है, इसलिए धारा 67क के तहत कोई अपराध नहीं है।
- 7.6 यह तर्क बिल्कुल सही है कि अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार कलात्मक रचनात्मकता और अभिव्यक्ति की रक्षा करता है।
- 7.7 अंत में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में सहनशीलता की उच्च सीमा लागू होनी चाहिए क्योंकि वेब-सीरीज़ "पुल मीडिया" का एक रूप है। पुल मीडिया में, उपभोक्ता के पास यह तय करने का अधिक विकल्प होता है कि वे कोई विशेष जानकारी देखना चाहते हैं या नहीं। टेलीविज़न या रेडियो के विपरीत, जहाँ अश्लील जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रसारित की जा सकती है और उपयोगकर्ताओं के पास यह चुनने का कोई विकल्प नहीं होता है कि कौन सी जानकारी उपलब्ध कराई जाए, इंटरनेट पर पुल मीडिया की खपत दर्शकों को इस बात पर पूर्ण नियंत्रण और निर्णय लेने का अधिकार देती है कि वे क्या देखते हैं। इसलिए, वेब-सीरीज़ केवल उन लोगों के लिए उपलब्ध और सुलभ है जो इसे देखना चाहते हैं, और इसलिए "पुल कंटेंट" पर अश्लीलता की उच्च सीमा लागू की जानी चाहिए।

8. *परिवादी की प्रस्तुतियाँ*: हमने विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद सिंह, अधिवक्ता-व्यक्तिगत रूप से को सुना है, जो परिवादी (प्रत्यर्थी सं. 2) हैं। उन्होंने तर्क दिया है कि वर्तमान मामला रद्द करने योग्य नहीं है। वेब-सीरीज़ की कथित जानकारी आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क के दायरे में आती है और महिलाओं के अश्लील चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 3 और 4 का भी उल्लंघन करती है, जिस पर उच्च न्यायालय विचार करने में विफल रहा है। सामुदायिक मानक परीक्षण और अवीक सरकार (पूर्वोक्त) और देवीदास रामचंद्र तुलजापुरकर बनाम महाराष्ट्र राज्य 18 में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वेब-सीरीज़ के उपर्युक्त भाग अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट हैं। सबसे पहले, जानकारी सेक्स में कामुक रुचि को आकर्षित करती है, जैसा कि समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाले औसत व्यक्ति द्वारा निर्धारित किया जाता है। एपिसोड के शीर्षक और कथानक यौन गतिविधि में संलग्न कॉलेज के छात्रों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। एपिसोड की जानकारी में यौन रूप से स्पष्ट भाषा और अपशब्दों का भी उपयोग किया गया है, जिसे "नया सामान्य" नहीं कहा जा सकता। दूसरा, जानकारी में यौन आचरण को स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक तरीके से दर्शाया गया है। तीसरा, जानकारी में गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य का अभाव है। चौथा, जानकारी यौन रूप से अशुद्ध विचारों को जगाने की प्रवृत्ति रखती है। पाँचवाँ, जानकारी सार्वजनिक हित या कला, साहित्य, विज्ञान के हित में नहीं है और इसलिए, अश्लीलता उचित नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी बताया है कि वर्तमान मामले में जानकारी इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है और बच्चों सहित किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ है और इसलिए इसे सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता के हित में विनियमित किया जाना चाहिए।

9. *विक्षेपणः* मुख्य मुद्दा यह है कि क्या वेब-सीरीज 'कॉलेज रोमांस' के एपिसोड के शीर्षक और जानकारी में अपशब्दों और अपवित्र भाषा का उपयोग आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67 क के तहत अश्लील और यौन रूप से स्पष्ट जानकारी के प्रकाशन और प्रसारण का अपराध है। हम धारा 67 के उद्देश्य के लिए 'अश्लीलता' और धारा 67 क के उद्देश्य के लिए 'यौन रूप से स्पष्ट जानकारी' के संदर्भ में इनमें से प्रत्येक प्रावधान की जांच करेंगे।

क. *क्या जानकारी 'अश्लील' है:*

10. हम सबसे पहले इस तर्क पर विचार करेंगे कि यह जानकारी अश्लील है। आईटी अधिनियम की धारा 67 इस प्रकार है:

67. इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करने के लिए दंड.- जो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में कोई ऐसी जानकारी प्रकाशित या प्रसारित करता है या प्रकाशित या प्रसारित करवाता है, जो कामुक है या कामुक रुचि को आकर्षित करती है या यदि इसका प्रभाव ऐसा है जो ऐसे व्यक्तियों को नष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित विषय को पढ़, देख या सुन सकते हैं, तो उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से, जो पांच लाख रुपये तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा और दूसरी या बाद की सजा की स्थिति में किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक हो सकता है, दंडित किया जाएगा।

11. इस न्यायालय ने भा.दं.सं. की धारा 292 के संदर्भ में यह निर्धारित करने के लिए अर्थ, परीक्षण, मानक और विधि निर्धारित की है कि क्या कोई जानकारी अश्लील है।
12. धारा 292 में 'अश्लील' को ऐसी पुस्तक, पैम्फलेट, कागज, लेखन, चित्र, पेंटिंग, चित्रण, आकृति या अन्य कोई वस्तु के रूप में परिभाषित किया गया है जो कामुक है, कामुक रुचि को आकर्षित करती है, या यदि समग्र रूप से देखा जाए तो इसका ऐसा प्रभाव है जो उन व्यक्तियों को नष्ट और भ्रष्ट करता है जो इसमें निहित जानकारी को पढ़ने, देखने या सुनने की संभावना रखते हैं। यह प्रावधान अश्लील जानकारी की बिक्री, वितरण, सार्वजनिक प्रदर्शन, संचलन, आयात, निर्यात आदि को अपराध मानता है। यह प्रावधान ऐसी जानकारी को बाहर करता है जब प्रकाशन को इस आधार पर सार्वजनिक भलाई के लिए उचित ठहराया जाता है कि यह विज्ञान, कला, साहित्य, या शिक्षा या सामान्य चिंता की अन्य वस्तुओं के हित में है; ऐसी जानकारी को धार्मिक उद्देश्यों के लिए रखा या उपयोग किया जाता है; इसे प्राचीन स्मारकों और मंदिरों पर या उन पर मूर्तिकला, उत्कीर्ण, चित्रित या चित्रित किया जाता है। धारा 292 का प्रासंगिक भाग संदर्भ के लिए उद्धृत किया गया है:

292. अश्लील पुस्तकों आदि की बिक्री आदि- (1) उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, कोई पुस्तक, पुस्तिका, कागज, लेख, रेखाचित्र, पेंटिंग, रूपांकन, आकृति या कोई अन्य वस्तु अश्लील समझी जाएगी यदि वह कामुक है या कामुक रुचि को आकर्षित करती है या यदि उसका प्रभाव, या (जहां उसमें दो या अधिक भिन्न वस्तुएं शामिल हैं) उसकी किसी एक वस्तु का प्रभाव, समग्र रूप से ऐसा है जो ऐसे व्यक्तियों को नष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखता है जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उसमें निहित

या सन्निहित विषय को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं या सुन सकते हैं।

यह स्पष्ट है कि धारा 292 और धारा 67 में "अश्लीलता" को समान रूप से परिभाषित किया गया है, जो कि:

- . कामुक; या
- . विवेकपूर्ण हित के लिए अपील; या
- . इसका प्रभाव भ्रष्ट और भ्रष्ट व्यक्तियों को प्रभावित करता है, जो सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें निहित या सन्निहित बात को पढ़ने, देखने या सुनने की सम्भाव्य रखते हैं।

हालांकि, उनके बीच अंतर केवल इतना है कि धारा 67 एक विशेष प्रावधान है जो तब लागू होता है जब अश्लील जानकारी इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित की जाती है। चूँकि कथित आपत्तिजनक जानकारी एक वेब-सीरीज़ है, इसलिए मामले पर आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत विचार किया जाना चाहिए, लेकिन धारा 292 के तहत निर्धारित अश्लीलता के लिए वही परीक्षण लागू होगा क्योंकि उस संबंध में प्रावधानों को समान रूप से लिखा गया है। इस संदर्भ में हम जाँच करेंगे कि अश्लीलता को कैसे समझा जाता है।

13. *न्यायिक उदाहरणों के माध्यम से विकास की पुनर्गणना*: इस न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध के रूप में धारा 292 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और [रंजीत डी उदेशी बनाम महाराष्ट्र राज्य](#) के निर्णय में यह निर्धारित करने के लिए हिकलिन परीक्षण लागू किया कि क्या 'लेडी चैटरलीज़ लवर' पुस्तक अश्लील थी। हिकलिन परीक्षण

के अनुसार, एक जानकारी अश्लील है यदि इसमें उन लोगों के दिमाग को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति है जो ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं और जिनके हाथों में प्रकाशन पड़ने की संभावना है:

... मैं समझता हूं कि अश्लीलता की कसौटी यह है कि क्या अश्लीलता के रूप में आरोपित विषय की प्रवृत्ति उन लोगों को नष्ट और भ्रष्ट करने की है जिनके मन ऐसे अनैतिक प्रभावों के लिए खुले हैं, और जिनके हाथों में इस प्रकार का प्रकाशन पड़ सकता है... यह पूरी तरह से निश्चित है कि यह किसी भी लिंग के युवाओं या यहां तक कि अधिक उम्र के व्यक्तियों के मन में सबसे अधिक अशुद्ध और कामुक चरित्र के विचारों का सुझाव देगा।"

14. यह परीक्षण अनैतिक प्रभावों द्वारा जानकारी को नष्ट और भ्रष्ट करने की क्षमता पर जोर देता है। इसे निर्धारित करने के लिए, न्यायालय को प्रत्येक कार्य पर एक बार में विचार करने के लिए खुद को लागू करना चाहिए। इसे पूरे कार्य की सेटिंग में अश्लील मामले का समग्र दृष्टिकोण लेना चाहिए, लेकिन अश्लील मामले पर अलग से भी विचार करना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यह इतना अश्लील है और इससे नष्ट और भ्रष्ट होने की संभावना है। केवल एक शब्द या महत्वहीन अंश जानकारी को अश्लील के रूप में योग्य बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कला और साहित्य में सेक्स और नग्नता को अपने आप में अश्लीलता के साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, जब तक कि कुछ और न हो। सेक्स को इस तरह से व्यवहार किया जाना चाहिए कि यह सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के लिए अपमानजनक हो, जब हमारे राष्ट्रीय मानकों के अनुसार आंका जाए, और यह कामुक, कामुक, यौन रूप से अपरिपक्व दिमागों को खुश करने की संभावना होनी चाहिए,

और इसे अश्लील होने के लिए "मानव प्रकृति के कामुक पक्ष" को आकर्षित करना चाहिए या अपील करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए।

15. न्यायालय ने एक ओर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कलात्मक स्वतंत्रता की रक्षा तथा दूसरी ओर सार्वजनिक शालीनता और नैतिकता के बीच एक नाजुक संतुलन बनाए रखने में अपनी भूमिका पर भी जोर दिया। इसने माना कि जब कला और अश्लीलता को मिलाया जाता है, तो कला इतनी प्रबल होनी चाहिए कि अश्लीलता छाया में चली जाए या तुच्छ और महत्वहीन हो और उसे अनदेखा किया जा सके। इसी तरह, यदि मामले में एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य और लाभ है जो जानकारी की अश्लीलता से अधिक है (जैसे चिकित्सा पाठ्यपुस्तकें), तो ऐसी जानकारी संवैधानिक रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता द्वारा संरक्षित है और इसे अश्लील के रूप में आपराधिक नहीं बनाया जा सकता है।

16. न्यायालय ने श्री चंद्रकांत कल्याणदास काकोडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में हिक्लिन परीक्षण और रंजीत उदेशी (सुप्रा) का अनुसरण किया लेकिन इसने कुछ चेतावनियाँ भी पेश कीं और परीक्षण को कुछ हद तक परिष्कृत किया। उस मामले की जानकारी, एक मराठी लघु कहानी शमा पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि पूरी कहानी को पढ़ने पर यह पोर्नोग्राफी या कामुक रुचि को बढ़ावा नहीं देती है। भले ही काम उच्च साहित्यिक गुणवत्ता का न हो और अपरिपक्व और खराब स्वाद का हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन लोगों को नष्ट या भ्रष्ट कर सके जिनके हाथों में यह पढ़ने की संभावना है, जिनमें किशोर भी शामिल हैं। न्यायालय ने यह भी आगाह किया कि कलाकार या लेखक के लिए मानक यह नहीं है कि किशोर मन को सेक्स के संपर्क में नहीं लाया जाना चाहिए या काम से सेक्स के सभी संदर्भों को मिटा दिया जाना चाहिए, भले ही यह प्रमुख विषय हो या नहीं। अश्लीलता के लिए परीक्षण में कहा गया था:

"हमें यह देखना है कि क्या एक वर्ग, एक अलग मामला नहीं, जिसके हाथों में यह पुस्तक, लेख या कहानी आती है, उसके नैतिक दृष्टिकोण पर असर पड़ता है या इसे पढ़ने से वे भ्रष्ट हो जाते हैं या उनके मन में अशुद्ध और कामुक विचार पैदा होते हैं।"

17. के.ए. अब्बास बनाम भारत संघ मामले में न्यायालय ने अश्लीलता निर्धारित करने के लिए परीक्षण और प्रक्रिया का सारांश इस प्रकार दिया:

- (1) कला और साहित्य में सेक्स और नग्नता को बिना किसी अतिरिक्त कारण के अश्लीलता का प्रमाण नहीं माना जा सकता है।
- (2) अनुमेय कार्रवाई की सीमा जानने के लिए एक पुस्तक की दूसरी पुस्तक से तुलना करना आवश्यक नहीं है।
- (3) क्या कलात्मक है और क्या अश्लील है, यह तय करने का नाजुक काम न्यायालयों द्वारा किया जाना है और अंतिम उपाय के रूप में, उच्चतम न्यायालय द्वारा, इसलिए अश्लीलता के प्रश्न पर साहित्यकारों या अन्य लोगों का मौखिक साक्ष्य प्रासंगिक नहीं है।
- (4) सम्पूर्ण कार्य के परिवेश में अश्लील विषय का समग्र दृष्टिकोण अवश्य आवश्यक है, किन्तु अश्लील विषय पर अलग से विचार किया जाना चाहिए, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वह इतना घिनौना है और क्या उसकी अश्लीलता इतनी निश्चित है कि वह उन लोगों को भ्रष्ट कर सकती है, जिनके मन इस प्रकार के प्रभाव के प्रति खुले हैं और जिनके हाथों में यह पुस्तक पढ़ने की संभावना है।

- (5) समकालीन समाज के हितों और विशेषकर उस पर पुस्तक के प्रभाव आदि को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
- (6) जहां अश्लीलता और कला का मिश्रण हो, वहां कला इतनी प्रबल होनी चाहिए कि अश्लीलता छाया में चली जाए या अश्लीलता इतनी तुच्छ और महत्वहीन हो जाए कि उसका कोई प्रभाव न रह जाए और उसे नजरअंदाज किया जा सके।
- (7) सार्वजनिक शालीनता या नैतिकता के लिए अपमानजनक तरीके से यौन व्यवहार करना, जो कि हमारे मौलिक कानून के शब्द हैं, जिन्हें हमारे राष्ट्रीय मानकों के आधार पर आंका जाता है और जो कि कामुक, कामुक या यौन रूप से अस्थिर दिमागों को जन्म देने वाला माना जाता है, के परिणाम का निर्धारण होना चाहिए।
- (8) जब विचारों, मतों और सूचनाओं या सार्वजनिक हितों या मुनाफे का प्रचार होता है, तो समाज के हित मुक्त भाषण और अभिव्यक्ति के पक्ष में तराजू को झुका सकते हैं। इस प्रकार चिकित्सा विज्ञान पर अंतरंग चित्रों और तस्वीरों वाली किताबें हालांकि एक तरह से अभद्र हैं, लेकिन उन्हें अश्लील नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन चिकित्सा पाठ के बिना पुस्तक के रूप में एकत्र किए गए समान चित्र और तस्वीरें निश्चित रूप से अश्लील मानी जाएंगी।
- (9) एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य या लाभ के बिना अश्लीलता को बोलने या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संवैधानिक संरक्षण नहीं मिल सकता है। अश्लीलता का अर्थ है यौन

संबंधों के साथ इस तरह से पेश आना जो मानव स्वभाव के कामुक पक्ष को आकर्षित करता हो या उसमें वह प्रवृत्ति हो। यौन संबंधों के साथ ऐसा व्यवहार विनम्रता और शालीनता के लिए अपमानजनक है।

(10) ज्ञान दोषी कृत्य का हिस्सा नहीं है। पुस्तक की अश्लीलता के बारे में अपराधी का ज्ञान कानून के तहत आवश्यक नहीं है और यह सख्त दायित्व का मामला है।

18. समरेश बोस (पूर्वोक्त) में, जिस पर अपीलार्थीगण ने भरोसा किया है, इस न्यायालय ने अशिष्टता और अश्लीलता में अंतर किया है। इस मामले में विचाराधीन जानकारी 'प्रजापति' नामक एक बंगाली उपन्यास था। न्यायालय ने नोट किया कि पुस्तक में यौन क्रियाओं के सुझावों के साथ-साथ अपशब्दों और अपरंपरागत शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन सेक्स के किसी भी प्रत्यक्ष कृत्य का वर्णन नहीं किया गया था। ये शब्द अश्लील हैं और घृणित और वितृष्णा की भावना पैदा करते हैं और पाठक को चौंका सकते हैं लेकिन यह जरूरी नहीं कि अश्लीलता हो, जो भ्रष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति है। इसने माना कि अपशब्दों और अपरंपरागत शब्दों का उपयोग; सेक्स पर जोर; महिला शरीर का वर्णन; और उपन्यास में अश्लील भाषा में भावनाओं, विचारों और कार्यों का वर्णन जानकारी को अश्लील नहीं बनाता है। इसके अलावा, केवल सेक्स का संदर्भ अश्लीलता के लिए पर्याप्त नहीं है और यह जानकारी को किशोरों के लिए अनुपयुक्त नहीं बनाता है।

19. न्यायालय ने उस प्रक्रिया का भी सारांश दिया जिसका पालन निष्पक्ष रूप से यह आकलन करने के लिए किया जाना चाहिए कि कोई जानकारी अश्लील है या नहीं। इसने माना कि न्यायाधीश को सबसे पहले खुद को

लेखक की स्थिति में रखना चाहिए ताकि वह उसके दृष्टिकोण को समझ सके और वह क्या संदेश देना चाहता है और क्या इसका कोई साहित्यिक या कलात्मक मूल्य है। फिर न्यायाधीश को खुद को हर आयु वर्ग के पाठक की स्थिति में रखना चाहिए जिनके हाथों में पुस्तक (या जानकारी) पढ़ने की संभावना है और ऐसे व्यक्तियों के दिमाग पर जानकारी के संभावित प्रभाव या प्रभाव का निर्धारण करना चाहिए। प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:

29. ...जैसा कि इस न्यायालय के पहले उल्लेखित दोनों निर्णयों में कहा गया है, "यह प्रश्न कि कोई विशेष लेख या कहानी या पुस्तक अश्लील है या नहीं, पूरी तरह से मौखिक साक्ष्य पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यह सुनिश्चित करना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या किताब या कहानी या उसका कोई अंश भा.दं.सं. की धारा 292 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या नहीं। किसी पुस्तक, कहानी या लेख की अश्लीलता के प्रश्न का निर्णय करने में न्यायालय जिसकी जिम्मेदारी इस प्रश्न का निर्णय करना है, यदि न्यायालय इसे आवश्यक समझता है, तो वह अपने मूल्यांकन और अपने विवेक की संतुष्टि के लिए, यदि उपलब्ध हो, तो साक्ष्य और प्रमुख साहित्यिक व्यक्तित्व के विचारों पर एक सीमा तक भरोसा कर सकता है। न्यायालय का निर्णय अनिवार्य रूप से पुस्तक या कहानी या लेख के समग्र रूप से वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन पर और पुस्तक, कहानी या लेख में शिकायत किए गए अंशों के विशेष संदर्भ में होना चाहिए। न्यायालय को पूरे कार्य की सेटिंग में अश्लीलता के रूप में शिकायत की गई विषय-वस्तु का समग्र दृष्टिकोण लेना चाहिए, लेकिन अश्लीलता के रूप में आरोपित विषय-वस्तु पर भी अलग से विचार किया जाना चाहिए ताकि पता लगाया जा सके कि क्या यह इतना घिनौना है और इसकी अश्लीलता इतनी स्पष्ट

है कि यह उन लोगों को नष्ट और भ्रष्ट कर सकता है जो इस तरह के प्रभाव के लिए स्वतंत्र विचारों वाले हैं और जिनके हाथों में यह पुस्तक पढ़ने की संभावना है। यद्यपि न्यायालय को इस प्रश्न पर ध्यानपूर्वक वस्तुनिष्ठ रूप से विचार करना चाहिए, फिर भी वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के मामले में मामले की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का व्यक्तिपरक दृष्टिकोण, भले ही अनजाने में, उसके दिमाग और प्रश्न पर उसके निर्णय को प्रभावित करने की संभावना है। शुद्धतावादी और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण वाला कोई न्यायाधीश किसी पुस्तक या कहानी या लेख के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर उसे अक्षील मान सकता है। यह संभव है कि एक अलग तरह के दृष्टिकोण वाला दूसरा न्यायाधीश उसी पुस्तक के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर उसी पुस्तक को अक्षील न माने। अक्षीलता की अवधारणा बहुत हद तक उन लोगों के सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावित होती है, जिनसे आम तौर पर पुस्तक पढ़ने की अपेक्षा की जाती है। यह निर्विवाद है कि विभिन्न देशों में समकालीन समाज की नैतिकता के मानकों के आधार पर अक्षीलता की अवधारणा आम तौर पर अलग-अलग देशों में अलग-अलग होती है। हमारी राय में, अक्षीलता के प्रश्न पर निर्णय करते समय, न्यायाधीश को सबसे पहले खुद को लेखक की स्थिति में रखने की कोशिश करनी चाहिए और लेखक के दृष्टिकोण से न्यायाधीश को यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि लेखक क्या संदेश देना चाहता है और क्या लेखक जो संदेश दे रहा है उसका कोई साहित्यिक और कलात्मक मूल्य है। इसके बाद न्यायाधीश को खुद को हर आयु वर्ग के पाठक की स्थिति में रखना चाहिए, जिनके इसके पाठक बनने की संभावना है और उन्हें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि पाठकों के मन में पुस्तक का किस तरह का संभावित प्रभाव पड़ने

की संभावना है। इसके बाद न्यायाधीश को पूरी तरह से पुस्तक के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन और अलग-अलग अक्षील कहे जाने वाले अंशों के द्वारा यह तय करने के लिए अपने न्यायिक दिमाग का निष्पक्ष रूप से इस्तेमाल करना चाहिए कि क्या विचाराधीन पुस्तक को भा.दं.सं. की धारा 292 के अर्थ में अक्षील कहा जा सकता है। उचित मामलों में, न्यायालय, किसी भी व्यक्तिपरक तत्व या व्यक्तिगत पसंद को खत्म करने के लिए, जो अवचेतन मन में छिपी रह सकती है और अनजाने में एक उचित उद्देश्य मूल्यांकन को प्रभावित कर सकती है, रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का उपयोग कर सकती है और प्रतिष्ठित या मान्यता प्राप्त लेखकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों पर भी विचार कर सकती है। ऐसे प्रश्नों पर साहित्य का, यदि कोई हो, तो उसके स्वयं के विचार और संतुष्टि के लिए ताकि न्यायालय उचित मूल्यांकन करने के कर्तव्य का निर्वहन कर सके।"

20. न्यायालय ने फिर इस परीक्षण को संबंधित उपन्यास पर लागू किया। खुद को लेखक की स्थिति में रखकर और उसके दृष्टिकोण से काम का मूल्यांकन करके, न्यायालय ने पाया कि उसका इरादा सामाजिक बुराईयों और बीमारियों को उजागर करना था, जिसके लिए लेखक ने अपनी तकनीक का इस्तेमाल किया है। इसी तरह, न्यायालय ने खुद को उन पाठकों की स्थिति में रखा जो पुस्तक को पढ़ने की संभावना रखते हैं। इसने माना कि पुस्तक को "दोनों लिंगों और किशोरों और वृद्धों के बीच सभी उम्र के पाठकों" द्वारा पढ़े जाने की संभावना है और पाया कि हालांकि यह सदमे और घृणा की भावना पैदा कर सकती है, लेकिन कोई भी पाठक पुस्तक को पढ़कर भ्रष्ट, अपमानित या कामुकता के लिए प्रोत्साहित नहीं होगा।

21. बाँबी कला इंटरनेशनल (पूर्वोक्त) में न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या फिल्म 'बैंडिट क्वीन' के कुछ दृश्य जिनमें बलात्कार और नग्नता को दर्शाया गया था, अश्लील थे। यहाँ, अश्लीलता को धारा 292 के तहत नहीं बल्कि सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत सेंसर बोर्ड प्रमाणन के लिए 1991 के दिशानिर्देशों के तहत माना गया था। न्यायालय ने रंजीत उदेशी (पूर्वोक्त) और चंद्रकांत कल्याणदास (पूर्वोक्त) में निर्धारित हिक्लिन परीक्षण का हवाला नहीं दिया या उसका पालन नहीं किया। इसके बजाय, इसने दिशानिर्देशों पर भरोसा किया और अश्लीलता के लिए निम्न प्रकार से परीक्षण निर्धारित किया:

22. उपर्युक्त दिशा-निर्देश सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं। इनमें फिल्म प्रमाणन से संबंधित अधिकारियों से समाज के मूल्यों और मानकों के प्रति उत्तरदायी होने और सामाजिक परिवर्तन पर ध्यान देने की अपेक्षा की गई है। उन्हें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि "कलात्मक अभिव्यक्ति और रचनात्मक स्वतंत्रता पर अनुचित रूप से अंकुश न लगाया जाए"। फिल्म को "इसके समग्र प्रभाव के दृष्टिकोण से इसकी संपूर्णता में आंका जाना चाहिए"। इसे दर्शाए गए काल और इससे संबंधित लोगों के समकालीन मानकों के प्रकाश में भी आंका जाना चाहिए, लेकिन इससे दर्शकों की नैतिकता को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। खंड 2 में यह अपेक्षा की गई है कि अश्लीलता, अश्लीलता या अनैतिकता से मानवीय संवेदनाओं को ठेस न पहुंचे, महिलाओं को अपमानित करने वाले या उनका अपमान करने वाले दृश्य प्रस्तुत न किए जाएं और महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के दृश्यों से बचा जाए, लेकिन अगर ऐसे दृश्य विषय से संबंधित हैं, तो उन्हें न्यूनतम तक सीमित किया जाए और विशिष्ट न बनाया जाए।"

22. न्यायालय ने पहले फिल्म के कथानक और विषय पर समग्र रूप से विचार किया और फिर नग्नता और बलात्कार के अलग-अलग दृश्यों पर विचार किया। पूरी फिल्म और कथित आपत्तिजनक जानकारी को विशेष रूप से देखते हुए न्यायालय ने माना कि ये दृश्य आंसू, दया, भय और शर्म की भावना पैदा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में केवल विकृत मन ही जागृत हो सकता है और सेंसरशिप का उद्देश्य विकृत व्यक्ति की रक्षा करना या अति संवेदनशील व्यक्ति की संवेदनशीलता को कम करना नहीं है। इसके अलावा, हर रोज सुनाई देने वाले अपशब्दों और गालियों के इस्तेमाल को भी हानिरहित माना गया। न्यायालय ने फिल्म के व्यापक सामाजिक उद्देश्य और संदेश पर जोर दिया - बलात्कार की शिकार महिला के आघात और भावनात्मक उथल-पुथल को दिखाकर बलात्कार और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की निंदा करना और उसके प्रति सहानुभूति और बलात्कारी के प्रति घृणा पैदा करना। इस प्रकार, जानकारी को अश्लील नहीं माना गया।
23. इसी तरह, *दूरदर्शन महानिदेशालय बनाम आनंद पटवर्धन* मामले में न्यायालय ने यह निर्धारित करने के लिए 'समकालीन सामुदायिक मानकों' का परीक्षण लागू किया कि क्या कोई वृत्तचित्र दूरदर्शन पर प्रमाणन और प्रसारण के उद्देश्य से अश्लील है। अश्लीलता के लिए एक त्रिआयामी परीक्षण इस प्रकार तैयार किया गया:

(क) क्या "समकालीन सामुदायिक मानकों को लागू करने वाला औसत व्यक्ति" यह पाएगा कि समग्र रूप से लिया गया कार्य कामुक रुचि को आकर्षित करता है;

(ख) क्या कार्य में स्पष्ट रूप से आपत्तिजनक तरीके से, लागू राज्य कानून द्वारा विशेष रूप से परिभाषित यौन आचरण को दर्शाया या वर्णित किया गया है; और

(ग) क्या समग्र रूप से देखा जाए तो उस कार्य में गंभीर साहित्यिक, कलात्मक, राजनीतिक या वैज्ञानिक मूल्य का अभाव है।

24. न्यायालय ने *रमेश बनाम भारत संघ* के मामले पर भरोसा किया, जहां यह माना गया कि शब्दों के प्रभाव का मूल्यांकन एक उचित, दृढ़-चित्त, दृढ़ और साहसी व्यक्ति के मानकों से किया जाना चाहिए, न कि कमजोर और अस्थिर दिमाग वाले या हर शत्रुतापूर्ण दृष्टिकोण में खतरा महसूस करने वाले लोगों के दृष्टिकोण से। वृत्तचित्र को समग्र रूप से देखते हुए इसका संदेश निर्धारित किया जाना चाहिए, जिसे केवल कुछ अंशों को देखकर व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यह माना गया कि फिल्म सामाजिक बुराइयों को दर्शाती है और किसी भी व्यक्ति के कामुक हितों को पूरा करने का प्रयास नहीं करती है।

25. अश्लीलता निर्धारित करने के कानून को *अजय गोस्वामी बनाम भारत संघ* मामले में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है और दोहराया गया है, जहाँ न्यायालय ने भारतीय पूर्ववर्ती और अमेरिकी न्यायशास्त्र दोनों का हवाला दिया है। इस निर्णय से जो सिद्धांत निकाले जा सकते हैं, वे इस प्रकार हैं:

- i. अश्लीलता का मूल्यांकन समकालीन रीति-रिवाजों और राष्ट्रीय मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए।
- ii. काम को समग्र रूप से परखा जाना चाहिए और कथित आपत्तिजनक जानकारी की भी अलग से जांच की जानी चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे इतनी अश्लील हैं कि वे पाठक या दर्शक को भ्रष्ट कर सकती हैं। जानकारी के साथ निकट और प्रत्यक्ष संबंध रखने वाला स्पष्ट और मौजूदा खतरा होना चाहिए।

- iii. सभी सेक्स-उन्मुख जानकारी और नग्नता हमेशा अश्लील नहीं होती है।
- iv. काम के प्रभाव का आंकलन एक औसत वयस्क व्यक्ति के मानक से किया जाना चाहिए। बच्चों के लिए क्या उपयुक्त है, इस मानक से विषय-वस्तु को विनियमित नहीं किया जा सकता क्योंकि तब वयस्क आबादी केवल वही पढ़ने और देखने के लिए प्रतिबंधित होगी जो बच्चों के लिए उपयुक्त है। इसी तरह, जानकारी का विनियमन एक अतिसंवेदनशील व्यक्ति के मानक के अनुसार नहीं हो सकता है और इसे "सामान्य ज्ञान और विवेक वाले सामान्य व्यक्ति" के अनुसार आंका जाना चाहिए।
- v. जहाँ कला और अश्लीलता का मिश्रण हो, वहाँ यह देखा जाना चाहिए कि क्या काम की कलात्मक, साहित्यिक या सामाजिक योग्यता उसकी अश्लीलता से अधिक है और अश्लील जानकारी को महत्वहीन या तुच्छ बनाती है। दूसरे शब्दों में, काम को संवैधानिक रूप से मुक्त भाषण के रूप में संरक्षित करने के लिए एक प्रमुख सामाजिक उद्देश्य या लाभ होना चाहिए। इसी तरह, जब जानकारी सार्वजनिक हित के विचारों, राय और सूचनाओं का प्रचार करती है, तो एक अलग दृष्टिकोण का उपयोग करना पड़ सकता है क्योंकि तब समाज का हित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के पक्ष में संतुलन को झुका देगा (उदाहरण के लिए, चिकित्सा पाठ्यपुस्तकों के साथ)।
- vi. न्यायालय को यह संतुलन बनाने का काम करना चाहिए कि क्या कलात्मक है और क्या अश्लील। इस नाजुक काम को करने के लिए, वह साहित्य के लोगों, प्रतिष्ठित और मान्यता प्राप्त

लेखकों के साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अश्लीलता है या नहीं।

26. एस. खुशबू बनाम कन्निअम्मल मामले में, मुद्रा भा.दं.सं. की धारा 292 के तहत अपीलार्थी के खिलाफ एक पत्रिका में दिए गए साक्षात्कार के लिए दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने से संबंधित था, जिसमें उसने विवाह पूर्व यौन संबंधों, विशेष रूप से लिव-इन संबंधों में, की सामाजिक स्वीकृति की मांग की थी और महिलाओं को अवांछित गर्भधारण और यौन संचारित संक्रमणों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा लेने के लिए आगाह किया था। न्यायालय ने माना कि धारा 292 के तहत कोई अपराध नहीं बनता क्योंकि जानकारी कामुक नहीं है (यानी यौन इच्छा व्यक्त करना या पैदा करना); कामुक रुचि (यानी यौन मामलों में अत्यधिक रुचि) को आकर्षित नहीं करती है; और इसका उन लोगों को भ्रष्ट करने का प्रभाव नहीं है जो जानकारी को पढ़ने, सुनने या देखने की संभावना रखते हैं। यह दोहराया गया कि ऐसे संदर्भ के संदर्भ की जांच किए बिना केवल सेक्स का संदर्भ जानकारी को अश्लील नहीं बनाता है। न्यायालय ने माना कि अश्लीलता का आकलन "समकालीन सामुदायिक मानकों के आधार पर किया जाना चाहिए जो औसत विवेकशील व्यक्ति की संवेदनशीलता और सहनशीलता के स्तर को दर्शाता हो।" इस मामले में, अपीलार्थी ने किसी भी यौन क्रिया का वर्णन नहीं किया था या ऐसा कुछ भी नहीं कहा था जो किसी विवेकशील और समझदार पाठक के मन में यौन इच्छा को जगाए, जिससे जानकारी अश्लील हो। इसलिए इस न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द कर दिया।
27. अवीक सरकार (पूर्वोक्त) में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने स्पोर्ट्स वर्ल्ड और आनंदबाजार पत्रिका के पत्रिका कवर के खिलाफ धारा 292 के तहत एक प्राथमिकी को भी खारिज कर दिया, जिसमें टेनिस खिलाड़ी

बोरिस बेकर की अपनी मंगेतर के साथ नग्न तस्वीर थी, जो एक अंतरजातीय युगल हैं। न्यायालय ने माना कि किसी तस्वीर, लेख या पुस्तक को अश्लील ठहराते समय, "समकालीन रीति-रिवाजों और राष्ट्रीय मानकों का ध्यान रखना चाहिए, न कि संवेदनशील या संवेदनशील व्यक्तियों के समूह के मानक का।" न्यायालय ने माना कि हिकलिन परीक्षण लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह "संदर्भ से बाहर माने जाने वाले काम के अलग-अलग अंशों के आधार पर अश्लीलता का निर्णय करता है और सबसे संवेदनशील पाठकों, जैसे कि बच्चों या कमजोर दिमाग वाले वयस्कों पर उनके स्पष्ट प्रभाव के आधार पर निर्णय करता है।" यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी, जहां परीक्षण सबसे पहले तैयार किया गया था, न्यायालय अब हिकलिन परीक्षण लागू नहीं करती हैं और इसके बजाय रोथ बनाम संयुक्त राज्य अमेरिका में तैयार किए गए परीक्षण को लागू करती हैं जहां अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने माना था कि यौन संबंधी जानकारी तभी अश्लील है जब सामुदायिक मानकों के परीक्षण को लागू करके एक औसत व्यक्ति के नजरिए से देखा जाए तो उसमें कामुक विचारों को उत्तेजित करने की प्रवृत्ति हो। इसी तरह, कनाडा में, प्रमुख परीक्षण 'सामुदायिक मानकों की समस्या परीक्षण' है, जिसके अनुसार एक काम अश्लील के रूप में योग्य होता है जब सेक्स का शोषण इसकी प्रमुख विशेषता होती है और ऐसा शोषण अनुचित होता है। इन न्यायशास्त्रीय विकासों पर ध्यान देते हुए, *अवीक सरकार* में न्यायालय स्पष्ट रूप से हिकलिन परीक्षण से हटकर "सामुदायिक मानक परीक्षण" की ओर चला गया, जहां यह निर्धारित करने के लिए जानकारी को समग्र रूप से माना जाता है कि क्या विशिष्ट भागों में नष्ट और भ्रष्ट होने की प्रवृत्ति है।

28. इस परीक्षण को लागू करते हुए, यह माना गया कि नग्न/अर्ध-नग्न महिला की तस्वीर तब तक अश्लील नहीं होती जब तक कि वह यौन इच्छा को न जगाए या यौन इच्छा को खुलकर प्रकट न करे या कामुक विचारों को उत्तेजित करने की प्रवृत्ति न रखती हो। वर्तमान मामले में, अपने मंगेतर के साथ पोज दे रही महिला की मुद्रा और पृष्ठभूमि, जिसकी तस्वीर उसके पिता ने ली थी, में उन लोगों को भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति नहीं है जिनके हाथों में पत्रिका आएगी, जब रंगभेद, नस्लवाद के खिलाफ तस्वीर के व्यापक सामाजिक संदेश और सभी जातियों में प्रेम और विवाह को बढ़ावा देने के प्रकाश में विचार किया जाएगा। हम ध्यान दे सकते हैं कि इस न्यायालय ने *देवीदास रामचन्द्र तुलजापुरकर* (पूर्वोक्त) में सामुदायिक मानक परीक्षण का पालन किया।
29. अंत में, *एन. राधाकृष्णन बनाम भारत संघ* मामले में पुनः यह माना गया कि न्यायालय को किसी विकृत दर्शक की संवेदनशीलता से निर्देशित नहीं होना चाहिए तथा अश्लीलता का निर्णय करते समय सम्पूर्ण कृति की पृष्ठभूमि, उसके उद्देश्य तथा चरित्र के घटक तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए।
30. *वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए उपर्युक्त उदाहरणों में सिद्धांतों का अनुप्रयोग:* धारा 292 पर उदाहरणों का विस्तृत रूप से पता लगाने का उद्देश्य अश्लीलता के अपराध की आवश्यक जानकारी, परीक्षण और मानक की पहचान करना है जिसके द्वारा कथित रूप से अपमानजनक है जानकारी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, और मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य और वह प्रक्रिया जिस पर न्यायालय को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए भरोसा करना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए।

31. वेब-सीरीज के कथित आपत्तिजनक हिस्सों पर अक्षीलता का परीक्षण करने के लिए, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है।
32. उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कथित तौर पर *अवीक सरकार* (पूर्वोक्त) में निर्धारित सामुदायिक मानक परीक्षण को लागू किया। यह कानून की स्थिति को सही ढंग से बताता है कि यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कुछ जानकारी अक्षील है, निर्धारण का मानक एक सामान्य व्यक्ति का है, न कि किसी अतिसंवेदनशील व्यक्ति का।
33. *गलत सवाल, गलत जवाब*: हालांकि, उच्च न्यायालय ने जांच के लिए गलत तरीके से सवाल तैयार किया है। उच्च न्यायालय द्वारा तैयार किया गया मुद्दा यह है कि क्या इस प्रकरण में इस्तेमाल की गई भाषा युवाओं द्वारा समकालीन रूप से इस्तेमाल की गई है और क्या यह शालीनता की सीमा को पूरा करती है। उच्च न्यायालय ने जांच के लिए निम्नलिखित शब्दों में सवाल तैयार किया है:

29. जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस न्यायालय ने मामले को अधिक प्रभावी ढंग से और निष्पक्ष रूप से तय करने के लिए वेब सीरीज कॉलेज रोमांस के कुछ एपिसोड और संबंधित एपिसोड देखे थे। उक्त वेब सीरीज को देखने के पीछे उद्देश्य निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करना था कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उठाया गया यह तर्क कि वेब सीरीज में इस्तेमाल की गई भाषा भाषा में है, या कॉलेजों में नई पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, या लॉ कॉलेजों में छात्र और कॉलेजों में युवा पीढ़ी केवल इसी भाषा का उपयोग करती है, बेबुनियाद है या नहीं।

30. यह न्यायालय एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति की व्यावहारिकता की कसौटी पर भी कसना/जांच करना चाहता था, स्वयं एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति के रूप में कार्य करते हुए, ताकि यह जांचा जा सके कि क्या ऐसी भाषा को वास्तव में एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति बिना शर्मिंदा हुए या इसे शालीनता या शालीनता की अवधारणा के विरुद्ध पाए बिना सुन सकता है...

(जोर दिया गया)

34. धारा 67 और उसमें 'अश्लील' के रूप में वर्णित जानकारी को सरलता से पढ़ने से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने गलत प्रश्न पूछा है, और स्वाभाविक रूप से वह गलत उत्तर पर पहुंचा है। आरंभ में, भा.दं.सं. की धारा 292 या आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत जांच इस बात पर निर्भर नहीं करती है कि भाषा या शब्द सभ्य हैं या नहीं, या क्या वे देश में आम तौर पर उपयोग किए जाते हैं। बल्कि, प्रावधान की सरल भाषा से, जांच यह निर्धारित करने के लिए है कि क्या जानकारी कामुक है, कामुक हितों को आकर्षित करती है, या उन लोगों के दिमाग को नष्ट और भ्रष्ट करने की प्रवृत्ति रखती है जिनके हाथों में यह पड़ने की संभावना है। उच्च न्यायालय ने गलत यात्रा शुरू की और गलत गंतव्य पर पहुंच गया।
35. अपशब्द अपने आप में अश्लील नहीं हैं: दूसरी सीमा त्रुटि उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष में है कि भाषा गालियों, अपशब्दों और अश्लील गालियों से भरी हुई है जिन्हें खुला न्यायालय में नहीं सुना जा सकता और यह भी कि यह युवाओं की भाषा नहीं है। इस निष्कर्ष के आधार पर, उच्च न्यायालय ने माना है कि जानकारी अश्लील है क्योंकि यह "प्रभावित करेगी और संवेदनशील दिमागों को नष्ट और भ्रष्ट करने की ओर प्रवृत्त करेगी"। अपने शब्दों में, उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

30. ...इस न्यायालय ने पाया कि वेब सीरीज में अभिनेता/नायक हमारे देश में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा यानी नागरिक भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। न्यायालय ने न केवल गाली-गलौज, अभद्र भाषा और अश्लील गालियों का अत्यधिक उपयोग पाया, बल्कि पाया कि वेब सीरीज में एक वाक्य में ऐसे कई शब्द थे और कुछ हिंदी वाक्य भी थे। विचाराधीन एपिसोड में, यौन रूप से स्पष्ट कृत्य का स्पष्ट वर्णन और संदर्भ है। न्यायालय को अपने चैंबर में इयरफोन की सहायता से एपिसोड देखना पड़ा, क्योंकि इस्तेमाल की गई भाषा की अभद्रता इस हद तक थी कि इसे आसपास के लोगों को चौंकाए बिना या चिंतित किए बिना नहीं सुना जा सकता था और भाषा की मर्यादा को ध्यान में रखना चाहिए जो एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति द्वारा बनाए रखी जाती है, चाहे वह पेशेवर हो या सार्वजनिक क्षेत्र में या यहाँ तक कि घर पर परिवार के सदस्यों के साथ भी। निश्चित रूप से, यह न्यायालय नोट करता है कि यह वह भाषा नहीं है जिसे देश के युवा या इस देश के अन्य नागरिक इस्तेमाल करते हैं, और इस भाषा को हमारे देश में अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा नहीं कहा जा सकता है।

36. जब श्रृंखला की संपूर्ण जानकारी को उपरोक्त के प्रकाश में देखा जाता है, तो यह किसी भी सामान्य व्यक्ति को इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि वेब श्रृंखला में इस्तेमाल की गई भाषा इस हद तक बेईमानी, अभद्र और अपवित्र है कि यह प्रभावित करेगी और संवेदनशील दिमागों को नष्ट और भ्रष्ट कर देगी। इसलिए, इस निष्कर्ष के आधार पर यह माना जा सकता है कि वेब श्रृंखला की जानकारी निश्चित रूप से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67 के तहत परिकल्पित आपराधिकता को आकर्षित करेगी।

(जोर दिया गया)

उच्च न्यायालय ने जिस विशिष्ट जानकारी को अश्लील पाया, यानी जो संवेदनशील दिमाग को नष्ट और भ्रष्ट करती है, वह "गंदी, अशिष्ट और अपवित्र" भाषा थी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उच्च न्यायालय ने अपवित्रता और अश्लीलता को अश्लीलता के बराबर माना है, बिना इस बात का उचित या विस्तृत विश्लेषण किए कि ऐसी भाषा अपने आप में यौन, कामुक, वासनामूलक या अपवित्र और भ्रष्ट कैसे हो सकती है। उद्धृत उदाहरणों से यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अश्लीलता और अपवित्रता अपने आप में अश्लीलता नहीं है। जबकि एक व्यक्ति को अश्लील और अपशब्दों से भरी भाषा अरुचिकर, अप्रिय, असभ्य और अनुचित लग सकती है, लेकिन यह अपने आप में 'अश्लील' होने के लिए पर्याप्त नहीं है। अश्लीलता ऐसी जानकारी से संबंधित है जो यौन और कामुक विचारों को जगाती है, जो कि एपिसोड में इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा या अपशब्दों का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं है। बल्कि, ऐसी भाषा घृणा, घृणा या सदमा पैदा कर सकती है। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष की वास्तविकता यह है कि एक बार जब उसने भाषा को अभद्र और अश्लील पाया, तो यह वास्तव में आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लीलता की आवश्यकताओं से दूर हो गया है। उच्च न्यायालय अपने निष्कर्षों में निहित विरोधाभास को नोटिस करने में विफल रहा।

36. *कोई वस्तुनिष्ठ विचार नहीं है:* तीसरा, उच्च न्यायालय ने यह आकलन करते समय कि क्या जानकारी अश्लील है या नहीं, अपने कानूनी दृष्टिकोण में गलती की है। समरेश बोस (पूर्वोक्त) में, इस न्यायालय ने बहुत गहराई और विस्तार से, प्रक्रिया और विधि निर्धारित की है जिसका पालन वस्तुनिष्ठ रूप से यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए कि क्या जानकारी अश्लील है या नहीं। न्यायालय को पूरे काम पर विचार करना

चाहिए और फिर पूरे काम के संदर्भ में कथित अश्लीलता वाले विशिष्ट अंशों पर विचार करना चाहिए ताकि निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। इसके अलावा, न्यायालय को सबसे पहले रचनाकार की स्थिति को समझना चाहिए कि वह काम से क्या संदेश देना चाहता है और क्या इसका कोई साहित्यिक या कलात्मक मूल्य है। फिर उसे पाठक या दर्शक की स्थिति में आना चाहिए जो काम का उपभोग करने की संभावना रखता है और ऐसे पाठक के दिमाग पर संभावित प्रभाव की सराहना करता है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले इस न्यायिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, जो इस प्रकार है:

43. मामले पर वापस आते हुए, याचिकाकर्ता की विशेष शिकायत यह है कि सीजन 01 के एपिसोड 05 में, 5 मिनट और 24 सेकंड से शुरू होकर 6 मिनट और 40 सेकंड तक और साथ ही 25 मिनट और 28 सेकंड से 25 मिनट और 46 सेकंड तक, पुरुष और महिला नायक की भाषा अश्लीलता, अश्लील शब्दों और अपशब्दों से भरी हुई है, बिना किसी चेतावनी या फ़िल्टर के दर्शकों की आयु पर प्रतिबंध लगाए कि जानकारी किसको दिखाई जानी चाहिए। सीजन 01 के एपिसोड 05 में इस्तेमाल की गई भाषा को इस न्यायालय ने सुना था, और इस्तेमाल की गई भाषा और वाक्यों की अश्लीलता का स्तर ऐसा था कि यह न्यायालय निर्णय के उद्देश्य से इसे अपने निर्णय में पुनः प्रस्तुत नहीं कर सकता। वेब सीरीज में ऊपर बताए गए समय पर इस्तेमाल की गई भाषा में मौखिक भाषा में यौन रूप से स्पष्ट कार्य को संदर्भित किया गया है। यह केवल एक अपशब्द नहीं है, बल्कि एक यौन रूप से स्पष्ट कार्य को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अपवित्र और अश्लील भाषा है जिसे निश्चित रूप से सामान्य या आम

तौर पर स्वीकृत भाषा नहीं कहा जा सकता है। बल्कि सीरीज में महिला नायक खुद पुरुष नायक पर आपत्ति जताती हुई और खुद भी पुरुष नायक के सामने वही भाषा दोहराकर इस भाषा के इस्तेमाल पर अपनी घृणा व्यक्त करती हुई सुनाई देती है। इसके जवाब में, पुरुष नायक और भी अधिक अश्लील अपशब्दों और अभद्र भाषा का उपयोग करता है, जिसे सार्वजनिक रूप से सुनने पर एक सामान्य विवेकशील व्यक्ति को घृणा होना स्वाभाविक है। बाद में उक्त एपिसोड में, महिला नायक दूसरों के लिए उसी अश्लील, यौन रूप से स्पष्ट भाषा का उपयोग करती है और पुरुष नायक उसके आचरण का आनंद लेता और उसकी सराहना करता हुआ दिखाई देता है। पुरुष नायक पुरुष और महिला जननांगों और यौन क्रिया का वर्णन करते हुए शब्दों का उपयोग करता है, इस प्रकार शब्दों के माध्यम से यौन रूप से स्पष्ट कार्य की तस्वीरें खींचता है जो इसे कामुक भावनाओं को जगाने के दायरे में लाता है। यह कहकर इससे कोई बच नहीं सकता कि उक्त कृत्य न तो किया गया, न दिखाया गया और न ही फिल्माया गया। चित्रण का मतलब केवल फिल्मांकन नहीं है, बल्कि एक माध्यम द्वारा संदेश देना है, जो इस मामले में बोली जाने वाली भाषा है। इसलिए, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई जानकारी आईटी अधिनियम की धारा 67 के साथ-साथ 67क के तहत निर्धारित अपराध को बढ़ाएगी।

(जोर दिया गया)

37. उपरोक्त अंशों से यह स्पष्ट है कि उच्च न्यायालय ने भाषा के अर्थ को उसके शाब्दिक अर्थ में लिया है, उस संदर्भ से बाहर जिसमें ऐसे अपशब्द बोले गए हैं। जबकि इस्तेमाल किए गए शब्दों का शाब्दिक अर्थ यौन प्रकृति का हो सकता है और वे यौन कृत्यों को संदर्भित कर सकते हैं,

उनका उपयोग सामान्य विवेक और सामान्य ज्ञान वाले किसी भी दर्शक में यौन भावनाओं या वासना को नहीं जगाता है। बल्कि, इन शब्दों का सामान्य उपयोग क्रोध, रोष, हताशा, शोक या शायद उत्तेजना की भावनाओं को प्रतिबिंबित करता है। इन शब्दों का शाब्दिक अर्थ लेने से, उच्च न्यायालय बड़ी वेब-सीरीज़ के संदर्भ में और "सामान्य ज्ञान और विवेक वाले सामान्य व्यक्ति" के मानक के अनुसार विशिष्ट जानकारी (अपवित्र भाषा) पर विचार करने में विफल रहा। जब हम वेब-सीरीज़ के कथानक और विषय के संदर्भ में ऐसी भाषा के उपयोग को देखते हैं, जो युवा छात्रों के कॉलेज जीवन पर एक मनोरंजक शो है, तो यह स्पष्ट है कि इन शब्दों का उपयोग सेक्स से संबंधित नहीं है और इसका कोई यौन अर्थ नहीं है। वेब-सीरीज़ के निर्माता ने न तो भाषा को उसके शाब्दिक अर्थ में लेने का इरादा किया था और न ही इसका उस समझदार दर्शक पर कोई प्रभाव पड़ेगा जो उस जानकारी को देखेगा। इसलिए, अश्लीलता का निर्धारण करने के लिए जानकारी का विश्लेषण और जांच करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए कानूनी दृष्टिकोण में स्पष्ट त्रुटि है।

38. इसके अलावा, जिस निष्पक्षता के साथ न्यायिक दिमाग से विचाराधीन कार्य की जांच करने की अपेक्षा की जाती है, वह पूरी तरह से खो गई जब उच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से न्यायालय कक्ष के माहौल से खुद को बाहर नहीं निकाल सका। उच्च न्यायालय की संवेदनशीलता और असुविधा तब स्पष्ट होती है जब उसने अभिनिर्धारित किया:

29. ...न्यायालय को अपने कक्ष में इयरफोन लगाकर यह एपिसोड देखना पड़ा, क्योंकि इस्तेमाल की गई भाषा इतनी अभद्र थी कि उसे आसपास के लोगों को चौंकाए या भयभीत किए बिना सुना नहीं जा सकता था और भाषा की उस मर्यादा को भी ध्यान में रखना था जिसे एक सामान्य

*विवेकशील व्यक्ति, चाहे वह पेशेवर हो या सार्वजनिक क्षेत्र में
या यहां तक कि घर पर परिवार के सदस्यों के साथ भी,
बनाए रखता है...*

39. *गलत मानक का अनुप्रयोग:* अंतिम मुद्दा उच्च न्यायालय द्वारा अश्लीलता निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानक या परिप्रेक्ष्य का है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि निर्धारण के लिए मानक किशोर या बच्चे का दिमाग या ऐसे अतिसंवेदनशील व्यक्ति नहीं हो सकते जो ऐसे प्रभावों के प्रति संवेदनशील हों। हालांकि, उच्च न्यायालय ने सामग्री के प्रभाव को मापने के लिए "प्रभावशाली दिमाग" के मानक का गलत तरीके से उपयोग किया है और इसलिए अश्लीलता के लिए परीक्षण को सही तरीके से लागू करने में गलती की है।
40. उच्च न्यायालय ने भाषा की शुद्धता को बनाए रखते हुए भाषाई शुद्धता, सभ्यता और नैतिकता को बनाए रखने की आवश्यकता पर कई टिप्पणियां की हैं और अपशब्दों से भरी भाषा के प्रतिनिधित्व को "नया सामान्य" बताया है। असली परीक्षा यह जांचना है कि क्या भाषा किसी भी तरह से आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत अश्लील है। जैसा कि पहले बताया गया है, उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण अप्रासंगिक विचारों पर आधारित है।
41. इसी तरह, किसी भी सामग्री की अश्लीलता और वैधता का आकलन करने का पैमाना यह नहीं हो सकता कि उसे न्यायालय की मर्यादा और अखंडता को बनाए रखते हुए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस तरह का दृष्टिकोण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अनुचित रूप से सीमित करता है जिसका प्रयोग किया जा सकता है और सामग्री के निर्माता को न्यायिक औचित्य, औपचारिकता और आधिकारिक भाषा की आवश्यकताओं को पूरा

करने के लिए बाध्य करता है। यहां भी, उच्च न्यायालय ने निर्णय लेने में गंभीर त्रुटि की।

42. उच्च न्यायालय ने युवाओं के लिए इंटरनेट पर वेब-सीरीज़ की मुफ्त उपलब्धता के बारे में भी चिंता और बेचैनी व्यक्त की है और कहा है कि इसे 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए प्रतिबंधित नहीं माना गया है। हालांकि ऐसी चिंता गलत नहीं है, लेकिन ऐसी सामग्री की उपलब्धता जिसमें अभद्र भाषा और अपशब्द शामिल हैं, उसे अश्लील के रूप में अपराध घोषित करके नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। यह एक असंगत और अत्यधिक उपाय है जो भाषण, अभिव्यक्ति और कलात्मक रचनात्मकता की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है।

43. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष सही नहीं था कि वेब-सीरीज़ में अश्लील सामग्री है और इसलिए आईटी अधिनियम की धारा 67 के प्रावधान लागू होते हैं।

ख. क्या धारा 67क के प्रयोजन के लिए जानकारी 'यौन रूप से स्पष्ट' है:

44. आईटी अधिनियम की धारा 67 क यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण को अपराध बनाती है। प्रावधान इस प्रकार है:

67क. इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण के लिए दंड।— जो कोई भी ऐसी सामग्री इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करता है या प्रकाशित या प्रसारित करवाता है जिसमें स्पष्ट यौन कृत्य या आचरण शामिल है, उसे पहली बार दोषी पाए जाने पर पांच वर्ष तक के कारावास और दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा और

*दूसरी या बाद की सजा पर सात वर्ष तक के कारावास और
दस लाख रुपये तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।*

45. उच्च न्यायालय ने इस बात पर कोई कारण नहीं बताया है कि धारा 67क वर्तमान मामले के तथ्यों के लिए कैसे आकर्षित होती है। हमारी राय में, धारा 67क का अपराध बिल्कुल भी नहीं बनता है।
46. वर्तमान मामले के तथ्य निश्चित रूप से धारा 67क को आकर्षित नहीं करते हैं क्योंकि परिवादी की शिकायत अश्लील गालियों, अपशब्दों और गालियों के अत्यधिक उपयोग के बारे में है। शिकायत में किसी भी 'यौन रूप से स्पष्ट कृत्य या आचरण' का कोई आरोप नहीं है और इस तरह, धारा 67क आकर्षित नहीं होती है।
47. धारा 67क किसी भी ऐसी सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशन, प्रसारण, प्रकाशन या प्रसारण को अपराध मानता है जिसमें यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण शामिल हो। हालांकि तीन अभिव्यक्तियाँ स्पष्ट, कार्य और आचरण खुले-बनावट वाली हैं और व्यापक अर्थ को समाहित करने में सक्षम हैं, लेकिन इस वाक्यांश को धारा 67 में दिए गए 'अश्लीलता' के संदर्भ में देखा जा सकता है। इस प्रकार, धारा 67क और धारा 67 के बीच एक संबंध हो सकता है। उदाहरण के लिए, यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण हो सकता है जो कामुक न हो। समान रूप से, ऐसा कार्य या आचरण कामुक हितों को आकर्षित नहीं कर सकता है। इसके विपरीत, कलात्मक या भक्ति रूप में प्रस्तुत किया गया यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण किसी व्यक्ति को भ्रष्ट करने के बजाय बिल्कुल विपरीत प्रभाव डाल सकता है।

ग. *प्राथमिकी रद्द करना:*

48. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी ऐसी सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण का कोई अपराध नहीं बनता है, जो अश्लील, कामुक या कामुक रुचि को आकर्षित करने वाली हो और/या जिसका प्रभाव नष्ट और भ्रष्ट व्यक्तियों पर हो, जैसा कि आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत प्रावधान है। इसी तरह, धारा 67क के तहत प्रावधान के अनुसार यौन रूप से स्पष्ट कार्य या आचरण वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण का कोई मामला शिकायत को मात्र पढ़ने से नहीं बनता है। यह तय है कि एक न्यायालय को एक प्राथमिकी या आपराधिक शिकायत को रद्द करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करना चाहिए, जब उसमें लगाए गए आरोप, प्रथम दृष्टया, किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं।
49. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम आपराधिक विविध मामला सं. 2399/2020, आपराधिक विविध मामला सं. 2215/2020 और आपराधिक विविध मामला सं. 2214/2020 में उच्च न्यायालय के दिनांक 06.03.2023 के निर्णय के खिलाफ अपील स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करते हैं, और यहां अपीलार्थीगण के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 और 67क के तहत पुलिस स्टेशन मुखर्जी नगर, दिल्ली में दिनांक 16.04.2023 को दर्ज प्राथमिकी 403/2023 को रद्द करते हैं।
50. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान कर दिया जाएगा।

के द्वारा हेडनोट्स तैयार किए गए: दिव्या पांडे मामले का परिणाम:

अपीलों की अनुमति दी गई।

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.